नईदुनिया

बांग्लादेश में रैपिड एक्शन बटालियन को खत्म करने की तैयारी

ढाका

बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) को खत्म करने जा रही है। गृह मंत्रालय के मसौदे के अनुसार, आरएबी के स्थान पर नए बल का गठन किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि 2004 में गठित रैपिड एक्शन बटालियन देश का विशिष्ट अर्धसैनिक बल है।

इसके पास मुख्य रूप से बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद को कुचलने और संगठित आपराधिक गतिविधियों को रोकने का जिम्मा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया से संबंधित सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित ढांचे के तहत नया बल आरएबी के कर्मचारियों, संपत्तियों और चल रहे अभियानों की जिम्मेदारी संभालेगा। नए बल का नाम स्पेशल रिस्पान्स बटालियन (एसआरबी) या पीपल्स प्रोटेक्शन फोर्सेज (पीपीएफ) दोनों में से एक हो सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इसके लिए नया कानून लाकर आरएबी को खत्म कर इसका पूरा ढांचा नए बल में समाहित कर दिया जाएगा।

गृह मंत्रालय के मसौदे की प्रस्तावना में कहा गया है कि नए बल में समाहित किए जाने वाले आरएबी के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तें जस का तस रहेंगी। नए कानून का मकसद बांग्लादेश पुलिस के तहत एक खास सहायक फोर्स बनाकर अंदरूनी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत और आरएबी को खत्म करना है। नए बल के सदस्यों के पास किसी जगह में घुसने, तलाशी लेने, संदिग्धों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थानों को देनी होगी।

आरएबी पर मानवाधिकार उल्लंघन के संगीन आरोप हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2021 में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए बल के सात मौजूदा और पुराने अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था। जुलाई में हुए बड़े विद्रोह के बाद जबरन गायब किए गए लोगों की जांच लिए गठित आयोग भी इस बल को खत्म करने की सिफारिश कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित सुधार का मकसद सिर्फ बल का नाम बदलना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा जवाबदेह और अधिकारों के प्रति संवेदनशील स्पेशल यूनिट बनाना है।

ह्यूमन राइट्स एंड पीस फार बांग्लादेश के अध्यक्ष एडवोकेट मंजिल मुर्शिद ने कहा कि बल का नाम बदलने से अधिक जरूरी है जवाबदेही पक्का करना। उन्होंने कहा कि आरएबी में अनुभवी लोग हैं। बल में आपरेशनल क्षमता है। सुधारों का फोकस गलत काम करने वालों को सजा दिलाने के साथ-साथ निगरानी को मजबूत करने पर होना चाहिए।

न्यूज ब्रीफ

80 साल के हो गए ट्रम्प, फिर भी दुनिया के 16 नेताओं से हैं छोटे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 जून को अपना 80वां जन्मदिन मनाया और इसके साथ ही वे

पद पर रहकर 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बने। ट्रंप से पहले जो बाइडेन नवंबर 2022 में राष्ट्रपति रहते हुए 80 साल के हुए थे। हालांकि ट्रम्प दुनिया के सबसे उम्रदराज नेताओं में शामिल हैं, लेकिन वे अभी भी कई वैश्विक नेताओं से कम उम्र के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 186 देशों के राष्ट्रीय नेताओं में 16 इसतरह के नेता हैं जिनकी उम्र ट्रम्प से अधिक है। इस आधार पर ट्रम्प दुनिया के करीब 91 प्रतिशत राष्ट्रीय नेताओं से अधिक उम्र के माने जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान वैश्विक नेताओं की औसत आयु करीब 63 वर्ष है, जबकि ट्रम्प इस औसत से काफी ऊपर हैं। बात दें कि दुनिया के सबसे उम्रदराज मौजूदा राष्ट्रीय नेता कैमरून के राष्ट्रपति पाल बिया हैं, जिनकी आयु 93 वर्ष है। वे 1982 से सत्ता में बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद हैं, जिनकी उम्र 90 वर्ष है और वे 2015 से शासन कर रहे हैं। यानी सऊदी शासक ट्रम्प से करीब 10 वर्ष बड़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेताओं में बड़ी संख्या अफ्रीकी देशों की है। इसमें युगांडा, इक्वेटोरियल गिनी, मलावी, आइवरी कोस्ट, जिम्बाब्वे और रिपब्लिक आफ कांगो के नेता शामिल हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी 82 वर्ष के हैं और लगभग चार दशकों से सत्ता में हैं, जबकि इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति तेओदोरो ओबियांग न्गुएमा म्बासोगो 1979 से शासन कर रहे हैं। रिपोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है।

खतरनाक कछुआ तैरता हुआ देखा गया वेल्स की नदी में, मचा हडकंप

वेल्स। ब्रिटेन के वेल्स शहर में स्थित एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पाट पेनलेरगेयर वैली वुड्स के

जंगल के बीच बहने वाली एक शांत नदी में अचानक स्नैपिंग टर्टल प्रजाति का एक अत्यंत आक्रामक और खतरनाक कछुआ तैरता हुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के बीच भारी हड़कंप मच गया। डायनासोर के जमाने जैसा दिखने वाले इस रेंगने वाले जीव को देखकर लोगों में इस कदर खौफ फैल गया कि अधिकारियों को तुरंत एक इमरजेंसी सेफ्टी अलर्ट जारी करना पड़ा। प्रशासन ने स्थानीय तैराकों और अपने पालतू कुत्तों को यहां टहलाने वाले लोगों को पानी से पूरी तरह दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 35 सेंटीमीटर लंबा और तीन से चार साल पुराना यह कछुआ इंसानों और जानवरों को बेहद गंभीर चोट पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम था। यह लगभग एक किलो वजनी खतरनाक कछुआ, अपने नुकीले जबड़ों के लिए कुख्यात है, और इसे वन्यजीव विभाग की टीम ने एक कड़े और सूझबूझ भरे आपरेशन के बाद आखिरकार सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है। इस कछुए का नाम अब शीला रखा गया है। रेस्क्यू किए जाने के बाद इस शिकारी कछुए को करीब 220 मील दूर केंट शहर में स्थित नेशनल सेंटर फार रेप्टाइल वेलफेयर भेजा गया है, जहां डाक्टरों ने उसकी सेहत को बिल्कुल दुरुस्त बताया है। जीव विज्ञानियों के अनुसार, स्नैपिंग टर्टल मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि ब्रिटेन की इस नदी में यह कछुआ खुद से नहीं आया, बल्कि इसे किसी लापरवाह मालिक ने गैर-कानूनी तरीके से यहां लाकर लावारिस छोड़ दिया था, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। इस प्रजाति के कछुए अपने छुरे जैसी धारदार और चोंच जैसे मजबूत जबड़ों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं, जिसका एक वार इंसान को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकता है। रेप्टाइल सेंटर के डायरेक्टर क्रिस न्यूमैन ने इस जीव की ताकत का उदाहरण देते हुए बताया कि इस कछुए के काटने का बल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना हाथ कार के दरवाजे के बीच में रख दें और कोई उस दरवाजे को पूरी ताकत से बंद कर दे।

नेपाल के अनमोल गांव:स्विट्जरलैंड सा सौंदर्य, कम बजट में

काठमांडू। विदेश यात्रा का सपना देखकर अक्सर मन में स्विट्जरलैंड, फ्रांस या इटली जैसे देशों की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी इसतरह के कई खूबसूरत गांव मौजूद हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और विहंगम हिमालयी दृश्यों के मामले में किसी भी प्रसिद्ध यूरोपीय पर्यटन स्थल को टक्कर दे सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि नेपाल की यात्रा बेहद कम खर्च में पूरी की जा सकती है, जिससे यह परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए एक शानदार और किफायती विकल्प बन जाता है। ऊंचे हिमालय की चोटियां, हरे-भरे पहाड़, पारंपरिक घर, सदियों पुरानी बौद्ध संस्कृति और मनमोहक घाटियां नेपाल के ग्रामीण इलाकों की पहचान हैं। यहां का हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है और पर्यटकों को आधुनिक जीवन की आपाधापी से दूर प्रकृति तथा संस्कृति के करीब ले आता है। यहां के शांत वातावरण और स्थानीय आतिथ्य में अनूठी शांति मिलती है। इन खूबसूरत गांवों में से एक है चिसापानी, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारे देखे जा सकते हैं, जो वीकेंड ट्रिप और छोटे ट्रेक के लिए आदर्श बनाते हैं। वहीं, ऐतिहासिक बंदीपुर अपनी नेवारी संस्कृति और पारंपरिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी पत्थरों से बनी गलियां और पुराने घर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

नई वैश्विक जंग का बड़ा कारण बन सकता है एआई हथियार, क्लाड का दूसरे देश नहीं कर पाएंगे उपयोग

वाशिंगटन

दुनिया में तकनीकी वर्चस्व की नई प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इस दौड़ का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभरा है। इसी बीच अमेरिका ने अपनी प्रमुख एआई कंपनी ऐंथ्रापिक को निर्देश दिया है कि वह अपने कुछ अत्याधुनिक एआई माडल विदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध न कराए। इस कदम को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐंथ्रापिक का एआई माडल क्लाड दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन चर्चा उसके अधिक उन्नत माडलों मिथास और फेबल 5 को लेकर हो रही है। बताया जाता है कि मिथास कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों की पहचान करने में अत्यधिक सक्षम था और संवेदनशील नेटवर्क तक पहुंच बनाने की क्षमता रखता था। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए बाद के माडलों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिबंध जोड़े गए।

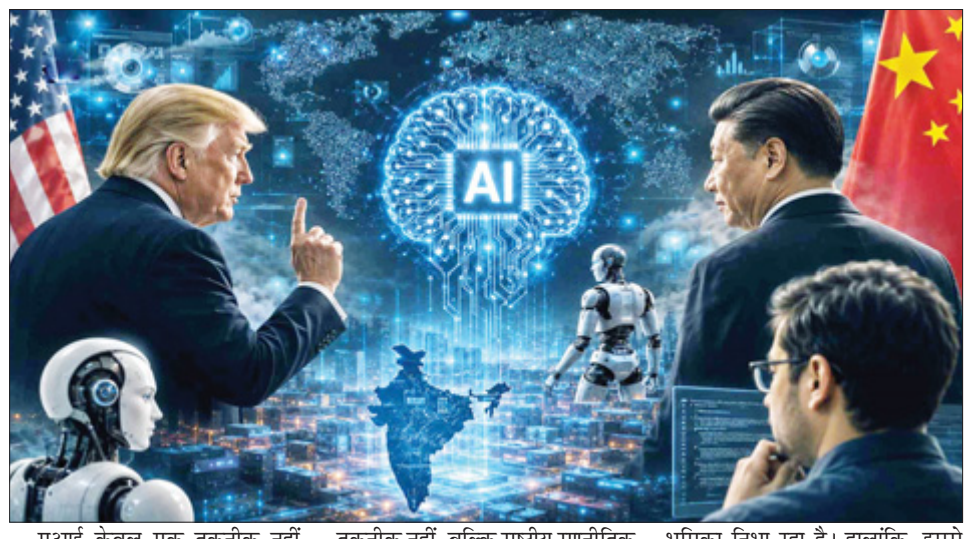

एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का आधार बन चुका है। यह तकनीक कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सीखने और काम करने में सक्षम बना रही है। मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करने से लेकर साफ्टवेयर कोड लिखने, वीडियो तैयार करने और जटिल दस्तावेज बनाने तक, एआई कई क्षेत्रों में तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो देश एआई तकनीक में आगे होगा, वह भविष्य की वैश्विक शक्ति संरचना में भी मजबूत स्थिति हासिल करेगा। अमेरिका के इस फैसले का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ उन्नत एआई माडलों तक विदेशी नागरिकों, कंपनियों और यहां तक कि अमेरिका में कार्यरत गैर-अमेरिकी कर्मचारियों की पहुंच भी सीमित की जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि एआई को अब केवल व्यावसायिक तकनीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, एआई माडल तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा कहां से आ रहा है सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में वास्तविक जीवन से जुड़े डेटा की जरूरत होती है। इसके लिए कई कंपनियां विकासशील देशों में लोगों की दैनिक गतिविधियों को रिकार्ड कर रही हैं। कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर घरेलू कामकाज करने वाले लोगों तक, विभिन्न गतिविधियों के वीडियो और व्यवहार संबंधी डेटा का उपयोग रोबोट और एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने में किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे डेटा का संग्रहण विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अपेक्षाकृत कम लागत पर संभव है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों का डेटा वैश्विक एआई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि, इससे डेटा स्वामित्व और तकनीकी लाभ के बंटवारे को लेकर नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन फिलहाल सबसे आगे माने जाते हैं, जबकि भारत अभी अपनी क्षमताओं को तेजी से विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में भारत के सामने चुनौती केवल नई तकनीक अपनाने की नहीं, बल्कि अपने डेटा संसाधनों, अनुसंधान क्षमता और एआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की यह प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार या तकनीकी उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नियंत्रण को लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगी। ऐसे में भारत के लिए आत्मनिर्भर एआई विकास और डेटा सुरक्षा रणनीति पर गंभीरता से काम करना समय की मांग बन गया है।

वैज्ञानिकों ने तैयार किया पृथ्वी के भीतर छिपे विशाल फंगल नेटवर्क का नक्शा

लंदन

पहली बार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भीतर छिपे एक विशाल फंगल नेटवर्क का वैश्विक नक्शा तैयार किया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंगस कहते हैं, जो पृथ्वी के लगभग 70 प्रतिशत पौधों की प्रजातियों से सीधा जुड़ा है। यह माइकोराइजल फंगस का नेटवर्क लगभग 110 कुआड्रिलियन किलोमीटर यानी 621 ट्रिलियन मील लंबा है। यह दूरी इतनी है कि इससे पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को करीब एक अरब बार तय किया जा सकता है। यह अंडरग्राउंड नेटवर्क लगभग 45 करोड़ साल से पौधों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसका कुल वजन दुनिया के सभी इंसानों के कुल वजन से छह गुना अधिक आंका गया है। नीदरलैंड की ब्रीज यूनिवर्सिटी और स्पन (सोसायटी फार द प्रोटेक्शन आफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स) के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के नौ अलग-अलग बायोम से मिट्टी के 16 हजार से अधिक सैंपल और मशीन लर्निंग की मदद से इस नेटवर्क की मैपिंग की है। यह फंगस मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेकर पौधों को देता है, बदले में पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण से बनी कार्बन देते हैं। सिर्फ एक चम्मच मिट्टी के अंदर ही लगभग 10 मीटर लंबा फंगस नेटवर्क मौजूद हो सकता है। यह अदृश्य प्रणाली हर साल पौधों से लगभग चार अरब टन कार्बन डाइआक्साइड सोखकर मिट्टी में जमा करती है, जो इंसानों द्वारा फैलाए जाने वाले कुल प्रदूषण का करीब 11 प्रतिशत है। मिट्टी के नीचे कार्बन और पोषक तत्वों का परिवहन 120 माइक्रोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होता है, जो मानवीय पैमाने पर लगभग 248 मील प्रति घंटे के बराबर है। शोध में एक सरप्राइजिंग तथ्य सामने आया कि इस नेटवर्क की सबसे ज्यादा सघनता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की बजाय घास के मैदानों में है। दुनिया के कुल फंगस बायोमास का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा केवल घास के मैदानों और प्रेयरीज में मौजूद है, जैसे फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स और एशिया के तिब्बती पठार। हालांकि, यह अदृश्य साम्राज्य अब खतरे में है। आधुनिक खेती के तरीकों, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कवकनाशकों का व्यापक उपयोग, साथ ही बार-बार जुताई से इस फंगस नेटवर्क की सघनता में औसतन 47 प्रतिशत की गिरावट आई है। जब पौधों को तैयार उर्वरक मिलते हैं, तो वे फंगस को कार्बन देना बंद कर देते हैं, जिससे मिट्टी की कार्बन जमा करने की क्षमता खत्म हो जाती है।

आस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज में 19 देशों की वायु सेनाएं होंगी शामिल

नार्दर्न टेरिटरी। अगले माह 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के बीच आस्ट्रेलिया के नार्दर्न टेरिटरी में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन किया जाएगा। रायल आस्ट्रेलियन एयर फोर्स (आरएएएफ) द्वारा आयोजित यह अभ्यास एक बार फिर वैश्विक सैन्य सहयोग और संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस बार 19 मित्र और साझेदार देशों के 100 से अधिक विमान और हजारों सैन्य कर्मी इसमें हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में ब्रुनेई, कनाडा, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाएं शामिल होंगी। तीन सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास दुनिया के सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा, जहां वास्तविक युद्ध जैसी जटिल परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। आरएएएफ के अनुसार, पिच ब्लैक 2026 का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना, रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना है।

भारत की सख्ती से नेपाली फैक्ट्रियों में लगा ताला, गोदामों में फंसी 7 लाख किलोग्राम चाय

काठमांडू

भारत की नई चाय आयात नीति ने नेपाल के चाय उद्योग के सामने संकट पैदा किया है। भारतीय चाय बोर्ड की सख्त जांच और गुणवत्ता नियमों के कारण नेपाल का चाय निर्यात करीब रुक गया है। इसके चलते पूर्वी जिलों इलाम और झापा में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इलाम में 53 चाय फैक्ट्रियों ने 15 जून से काम बंद किया है। इसके अलावा झापा में 30 फैक्ट्रियों ने कुछ दिनों में उत्पादन रोकने की घोषणा की है।

इन फैक्ट्रियों में काम बंद करने से सेक्टर पर निर्भर हजारों मजदूरों और किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ झापा में करीब 20000 मजदूर और किसान अपनी कमाई के लिए चाय उद्योग पर निर्भर हैं। नेपाली चाय उद्योग का कहना है कि 3 लाख किलोग्राम से ज्यादा नेपाली चाय भारतीय बाजार में पहुंच चुकी है लेकिन अनिवार्य क्वालिटी टेस्टिंग प्रक्रियाओं के कारण फंसी हुई है।

इसके अलावा 7 लाख किग्रा से ज्यादा प्रोसेस्ड चाय फैक्टरी के गोदामों में बिना बिकी पड़ी है। फैक्टरी मालिकों का कहना है कि बिक्री रुकने के कारण स्टोरेज की जगह भर गई है। इससे किसानों को हरी चाय की पत्तियों के लिए भुगतान करना मुश्किल हो गया है। सूर्योदय आर्थोडाक्स टी

प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिल्ली श्रेष्ठ ने कहा कि जब तक तैयार चाय नहीं बिक रही है, फैक्ट्रियां नहीं चल सकतीं। टी बोर्ड आफ इंडिया ने मिलावटखोरी रोकने के लिए 1 मई से स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) शुरू किया है। इसके तहत नेपाल से आने वाली हर चाय की खेप की क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। नेपाली चाय उत्पादकों का कहना है कि टेस्ट के नतीजे आने में दो हफ्ते से ज्यादा का समय लगता है। उस दौरान खेप बेची नहीं जा सकती। अगर कोई सैंपल टेस्ट में फेल हो जाता है, चाय को या वापस करना पड़ता है या नष्ट करना पड़ता है। इस संकट का असर हजारों चाय उत्पादक किसानों पर पड़ने की आशंका है। सिर्फ सूर्योदय नगरपालिका में 2995 किसान चाय की खेती से जुड़े हैं। यह नगरपालिका 33655 रोपनी जमीन पर हर साल लगभग 2 करोड़ किलोग्राम हरी चाय की पत्तियां पैदा करती है। नेपाली अधिकारियों के अनुसार, नेपाल हर साल 70 लाख किलोग्राम से ज्यादा आर्थोडाक्स चाय निर्यात करता है।

जी-7 सम्मेलन में दिखी भारतीय कूटनीति, पीएम मोदी ने ब्रिटेन, यूएई, जापान, मिस्र और केन्या के नेताओं से की मुलाकात

व्यापार, निवेश, नवाचार, एआई और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा

एवियन (फ्रांस)

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन बैठकों की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न देशों के साथ सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन संबंधों में पिछले एक वर्ष के दौरान आई मजबूती पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हालिया व्यापार समझौते ने आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोले हैं। बैठक में नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कौशल विकास, खेल तथा निवेश जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के प्रति वहां की सरकार द्वारा दिखाई जा रही संवेदनशीलता और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ बातचीत में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को विशेष बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके अलावा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ हुई बैठक में वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की साझा आकांक्षाओं और विकास संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी आपसी विश्वास और विकास सहयोग पर आधारित है तथा दोनों देश अपने नागरिकों के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करते रहेंगे। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इन बैठकों को भारत की सक्रिय वैश्विक कूटनीति और प्रमुख देशों के साथ बढ़ते सहयोग का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है।